

## यूक्रेन विवाद: अमेरिका और रूस में वर्चस्व की लड़ाई

Dr. Dhiraj Bakolia

Associate Professor, Department of Political Science, Govt. Lohia College, Churu, Rajasthan, India

### सार

पश्चिमी देशों की चिंताएं हैं कि अगर यह तनाव बढ़कर युद्ध की दहलीज़ तक पहुँचा तो इसकी आग पूरे यूरोप में फैल सकती है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने खराब हालात देखे नहीं गए होंगे।

पश्चिमी देशों की खुफिया संस्थाओं का अनुमान है कि यूक्रेन की सीमा पर टैंकों और तोपों के साथ रूस के अभी एक लाख सैनिक तैनात हैं। अमेरिका का मानना है कि जनवरी के अंत तक इसकी संख्या 1.75 लाख तक बढ़ सकती है। अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन पर रूस के किसी भी हमले के 'गंभीर आर्थिक परिणाम' होंगे लेकिन फिर भी रूस 'एक खेल खेलने' में लगा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को कहा कि उन्हें लगता है कि उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में 'दखल देंगे' लेकिन एक 'मुकम्मल जंग' से बचना चाहेंगे। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी दी है कि रूस 'जल्द ही' यूक्रेन पर हमला कर सकता है।

*How to cite this paper:* Dr. Dhiraj Bakolia "यूक्रेन विवाद: अमेरिका और रूस में वर्चस्व की लड़ाई" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-2, February 2022, pp.753-757, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd49314.pdf



Copyright © 2022 by author (s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)



एंटनी ब्लिंकन की शुक्रवार को रूसी विदेशी मंत्री के साथ मुलाकात होनी है। उधर, यूक्रेन की सीमा पर रूस ने बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती कर रखी है। मैंने जब इस बारे में यूरोपीय संघ के एक सीनियर डिप्लोमैट से जब बात की तो उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, "पूर्व युगोस्लाविया के विघटन के बाद यूरोप पहली बार जंग के मुहाने पर खड़ा है।" रूस और यूक्रेन के बीच तनाव 2013 से शुरू हुआ। - नवंबर 2013 में यूक्रेन की राजधानी कीव में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। यानुकोविच को रूस का समर्थन था, जबकि अमेरिका-ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। फरवरी 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा।

### परिचय

रूस-चीन गठबंधन, रूस से भारत के दशकों पुराने दोस्ताना रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। यूक्रेन के मुद्दे पर भारत अब तक तटस्थ रहा है, पर अमरीका और रूस के तनाव को कम करने के लिए यदि वह कोई पहल कर सकता है, तो फौरी तौर पर इस दिशा में सक्रियता दिखाई जानी चाहिए। यूक्रेन को लेकर अमरीका और रूस की तनातनी ने दुनिया में एक और युद्ध का खतरा खड़ा कर दिया है। अमरीका के बाद ब्रिटेन ने भी रूस को धमकाना शुरू कर दिया है।

ब्रिटेन की यह ताजा घोषणा आग में घी डालने जैसी है कि वह अगले हफ्ते यूरोप में कुछ कूटनीतिक और सैन्य कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि उनका देश नाटो के तहत बाल्टिक और पूर्वी यूरोप में तैनात अपने सैन्य दल को दोगुना करेगा। जाहिर है, यह तैयारी रूस के खिलाफ है। ब्रिटेन और कनाडा, यूक्रेन को हथियार और युद्ध का सामान पहले से दे रहे हैं, अमरीका भी 20 करोड़ डॉलर की सुरक्षा सहायता की

घोषणा कर चुका है। साफ है कि अमरीका व उसके सहयोगी देश यूक्रेन को युद्ध का नया अखाड़ा बनाने पर आमादा हैं। रूस नहीं चाहता कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अलग देश बना यूक्रेन किसी भी कीमत पर पश्चिमी देशों के हाथों में जाए। वर्चस्व बनाए रखना ही यूक्रेन को लेकर चल रही रस्साकशी

की असली जड़ है। अमरीका और रूस के बीच इसी तरह की वर्चस्व की लड़ाई अफगानिस्तान को तबाह कर चुकी है। सीरिया में भी दोनों महाशक्तियां वर्चस्व का खेल दिखाती रही हैं। वहां भी कई बेकसूरों की जान गई और एक बड़ी आबादी पलायन के लिए मजबूर हुई।[1]



सबसे बड़ा खतरा दुनिया के दो खेमों में बंटने का है। यूक्रेन के मुद्दे ने इसके लिए जमीन तैयार कर दी है। चीन ने रूस के समर्थन के संकेत देकर मामले को और गंभीर बना दिया है। जैसे यूक्रेन पर रूस अपना दबदबा चाहता है, चीन ने उसी तरह के अतिक्रमण के मंसूबे ताइवान को लेकर पाल रखे हैं। इन मंसूबों को भांपकर अमरीका को चेतावनी देनी पड़ी है कि चीन, यूक्रेन के मुद्दे को ताइवान से जोड़ने की कोशिश न करे। चीन जैसा अलोकतांत्रिक देश अगर रूस से नजदीकियां बढ़ाता है, तो बाकी दुनिया के साथ-साथ यह भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। रूस-चीन गठबंधन, रूस से भारत के दशकों पुराने दोस्ताना रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। यूक्रेन के मुद्दे पर भारत अब तक तटस्थ रहा है, पर अमरीका और रूस के तनाव को कम करने के लिए यदि वह कोई पहल कर सकता है, तो फौरी तौर पर इस दिशा में सक्रियता दिखाई जानी चाहिए।[2]

### विचार - विमर्श

पूर्व सोवियत रूस के दो अलग हुए भाई रूस (**Russia**) और यूक्रेन (**Ukraine**) अपनी सीमाओं पर सेनाओं की बड़े पैमाने पर तैनाती को लेकर आमने-सामने हैं। नाटो (**NATO**) सैन्य गठबंधन के नेता, अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने की योजना बना रहा है। हालांकि रूस ने इस तरह की किसी भी योजना से इनकार किया है। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था तभी से उसके और यूक्रेन के बीच तनाव बना हुआ है। बताया जा रहा है कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हाल ही में हुई एक बैठक में अमेरिका के विदेश सचिव एंटोनी ब्लिंकेन ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के सामने दोहराया था कि अमेरिका ने रूस को यूक्रेन के साथ पश्चिमी सीमा से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने का आह्वान किया है। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, ब्लिंकेन ने साफ कर दिया है कि अगर रूस अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी तैयार हैं और रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ब्लिंकेन की बातों से यह साफ नहीं था कि कीमत चुकाने से उनका क्या मतलब था। उनका मतलब किसी तरह की सैन्य प्रतिक्रिया से था या कुछ और।[3]



### परिणाम

यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 90 हजार से ज्यादा सैनिक सीमा पर जुटे हैं और उनके साथ बख्तरबंद गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां भी मौजूद हैं. इसी को लेकर यूक्रेन और नाटो गठबंधन चिंतित है कि रूस किसी तरह के आक्रमण की कोई योजना तो नहीं बना रहा है. उधर रूस का कहना है कि यूक्रेन ने 1 लाख 20 हजार सैनिकों को सीमा पर तैनात कर रखा है और वह पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र को दोबारा हासिल करने में लगा हुआ है. यूक्रेन ने इस आरोप को गलत ठहराया है.[4]



रूस और यूक्रेन के बीच मतभेद नस्लीय दावे के रूप में सामने आया है. वहीं विशेषज्ञ इस विवाद को भू राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं. यूक्रेन ना तो यूरोप यूनियन और न ही नाटो का हिस्सा है फिर भी उसकी पश्चिमी यूरोप और नाटो के साथ बढ़ती निकटता ने रूस के माथे पर शिकन ला दी है. और वह इसे अमेरिकी नेतृत्व में उसके प्रभावी क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप के रूप में देख रहा है. 2014 में रूस ने क्रीमिया पर तब कब्जा किया जब यूक्रेन की जनता यूरोपीय संघ के साथ गहरे आर्थिक संबंधों पर जोर दे रही थी. इस दिशा में उठाए गए कदम को यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने रद्द कर दिया था, जो भारी विरोध के चलते देश से भाग गए थे. एक महीने बाद मार्च, 2014 को रूस की सेना क्रीमिया में पहुंच गई और उस पर कब्जा कर लिया, और एक विवादित जनमत संग्रह के तहत यह दिखाया गया कि क्रीमिया की जनता ने रूस का समर्थन किया है.[5]





# यूक्रेन पर रूस और अमेरिका में ठनी



**जो बाइडेन**

रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो  
आर्थिक प्रतिबंध झेलना पड़ेगा

युद्ध की स्थिति में अमेरिका यूक्रेन  
को अतिरिक्त रक्षा सामग्री देगा



**व्लादिमीर पुतिन**

हमारी सेना अपने क्षेत्र में है और  
यूक्रेन को धमकी नहीं दी गई है

यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से  
रोकने की गारंटी दे अमेरिका

यूक्रेन ने इस मामले के चलते यूरोपीय संघ और नाटो से प्रतिबंध पैकेज तैयार करने और रूस के आक्रामक रवैये के खिलाफ सहयोग की गुजारिश की है. हालांकि रूस नाटो के दिए किसी भी झटके का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुतिन ने मास्को में कहा था कि नाटो की यूक्रेन में किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि वह पश्चिमी देशों से भरोसेमंद और दीर्घ अवधि सुरक्षा की गारंटी चाहेंगे और नाटो पूर्व की ओर अपने कदम बढ़ाने से खुद को रोकेगा. पुतिन ने कहा कि वो अमेरिका और उसके सहयोगियों से इस बारे में बात करेंगे जिसमें उन समझौतों पर जोर दिया जाएगा जो नाटो को पूर्व की ओर अपने कदम को बढ़ाने से रोक सके. जिससे रूस को अपने क्षेत्र में किसी की हस्तक्षेप की धमकी मिलती है. 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के साथ रूस और यूक्रेन में शांति कायम रखने को लेकर एक समझौता हुआ था जिसे मिन्स्क समझौता कहा गया था जो अभी भी जैसे तैसे कायम है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह यूक्रेन के प्रतिकूल था.[6]

## निष्कर्ष

अमेरिकी विदेश सचिव ब्लिंकेन ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा था कि रूस के यूक्रेन पर हमले की योजना के उनके पास पुख्ता सबूत हैं. उन्होंने

स्टॉकहोम में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि रूस भले ही यूक्रेन पर हमले से इनकार करे, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि वह (पुतिन) कम वक्त में ऐसा करने की क्षमता रखते हैं. ब्लिंकेन ने कहा कि

हमने साफ कर दिया है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो दृढ़ता से जवाब देंगे जिसमें आर्थिक प्रभाव भी शामिल होगा. अमेरिकी राजनयिक और सैन्य संस्थानों ने हालांकि यह साफ नहीं किया है कि प्रतिक्रिया किस तरह की होगी, बस ब्लिंकेन ने यह कहा कि इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे. वहीं अमेरिकी सैन्य चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख मार्क मिले ने कहा कि इस तरह से अमेरिका और नाटो देशों के सुरक्षा हित दांव पर लगे हैं, रूस ने ऐसे देश पर सैन्य कार्रवाई की थी जो 1991 से स्वतंत्र था. वहीं रूस का मानना है कि नाटो ने तनाव कम करने और खतरनाक घटनाओं से बचने की हमारे प्रस्तावों की रचनात्मक जांच से इनकार कर दिया है. वहीं गठबंधन का सैन्य ढांचा रूस की सीमाओं के करीब आ रहा है.

इसी बीच रूस और अमेरिका अपने अपने देशों में राजनयिकों के निष्कासन में लगे हुए हैं, रूस ने जहां रूसी विदेश मंत्रालय से अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को 31 जनवरी तक देश छोड़ने को कहा है. यह उन लोगों के लिए है जो तीन साल से मास्को में तैनात थे. वहीं अमेरिका में 27 रूसी राजनयिक और उनके परिवार 30 जनवरी तक अमेरिका छोड़ देंगे. इसके साथ ही क्रीमिया पर कब्जे के बाद से रूस पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, इसके अलावा यूक्रेन को सैन्य हथियारों की मंजूरी के साथ साथ अमेरिका ने एक अरब डॉलर की रक्षात्मक सहायता भी प्रदान की है. ऐसा कहा जा रहा है कि ब्लिंकेन और लावरोव की बैठक के बाद जल्दी ही पुतिन और जो बाइडेन संपर्क कर सकते हैं. रूस के

उप विदेश मंत्री सर्गेइ रयाबकोव ने कहा था कि संपर्क होना बहुत जरूरी है, हमारी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं. उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेनस्की ने भी रूस के साथ बातचीत पर जोर दिया है.[6]

### संदर्भ

- [1] [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua). पहुँचतिथी 2018-01-09.
- [2] "Ukraine", The World Bank, 2018, पहुँचतिथी 12 अगस्त 2018 download: CSV XML EXCEL
- [3] "GINI index (World Bank estimate) | Data". [data.worldbank.org](http://data.worldbank.org) (English में). पहुँचतिथी 2018-01-08.
- [4] "Human Development Report 2018 - "Human Development for Everyone"" (PDF). मानव विकास रपट, यूएनडीपी. पप. 198-201. पहुँचतिथी 8 जनवरी 2018.
- [5] ↑[Rada Decision: Ukraine will change to winter time on 30 October] (Ukrainian में). [korrespondent.net](http://korrespondent.net). 18 October 2011. पहुँचतिथी 31 अक्टूबर 2011.
- [6] About introduction of changes and additions to the Constitution of Ukrainian SSR Verkhovna Rada.